[Shri Mohd. Shafi Qureshi]

persons excepting one who has not been indentified so far, and Rs. 400 to each of the two grievously injured persons has been made. The General Manager has also sanctioned a special posthumous grant of Rs. 2,000 in respect of the dead persons who have been identified.

Additional Commissioner of Railway Safety is expected to commence his statutory enquiry into this accident on 27th August, 1974.

17.40 hrs.

DISUSSION RE. FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY—contd.

श्री गेंदा सिंह (पदरौना) : सभापति महोदय, में श्री पन्त का ध्यान बाढ़ और सूखा सम्बन्धी कुछ वातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमारा ज़िला देवरिया कुछ सग्य से बाढ़ और सूखे से पीड़ित रहा हैं । 1971-1972 और 1973 का नक्शा मेरे सामने है । 1973–74 और 1974–75 में बाढ़ से जो नुक्सान हुआ है, उस के आंकड़े मेरे पास मौजूद नहीं हैं । केवल पिछले वर्ष 1.29 करोड़ रुपये का नुक्सान एक छोटे से ज़िले देवरिया में हुआ और 26 लाख लोग पीड़ित हुए । उस बाढ़ में 34, 35 आदमी मरे, यह सरकार कहती है, हालांकि वहां पचासों आदमी मर गये ।

इस बरस भी वहां अपार क्षति हुई है । सेशन के होते हुए मैं खुद वहां गया और म ने कुछ घूम कर देखा । आज लोग जिस दुर्गति में हैं, उस को मैं बयान नहीं कर सकता हूं । में एक लम्बे काल से पब्लिक वर्कर रहा हूं । अगर मेरी शारीरिक स्थिति अच्छी होती तो में यहां नहीं बैठता मैं उन लोगों की सेवा में लगा होता । दो तीन बरस पहले से जो लोग क्षतिग्रस्त थे, वे इस वर्ष की क्षति को उठाने में असमर्थ हैं । अगर मैं कहूं कि भूख से मौत हुई हैं, तो वह कुछ अत्युक्ति नहीं होगी ।

मैं जानता हूं कि श्री पन्त किस दिल के आदमी हैं । वह उन पन्त जी के लड़के हैं, जिन्होंने बड़ी गंडक नहर की नींव डाली थी, और अरबों रुपये खर्च कर के देवरिया, छपरा, मोतिहारी जिलों की सहायता की थी। गोरखपुर और तिरहुत डिविजन, बिहार के चार ज़िले और चार ज़िले यू० पी० के, यह घनी आबादी का क्षेत्र है, जिस की तुलना चाइना की जनसंख्या से की जा सकती है । उसी तरह सब बिगड़ी हुई नदियां वहां इकट्ठी होती हैं । उन में एक नदी बड़ी गंडक है, जिस को ग्रेट गंडक कहते हैं । सभापति महोदय, वह ग्रेट गंडक आप के ज़िले मुज़फ्फ़रपुर, और चम्पारन तथा छपरा के किनारे किनारे आती है, और वह समूचे देवरिया को छूती है। उस ने हमारे ज़िले को वर्बाद कर दिया है । देवरिया में 542 मिलीमिटर पानी बरसा है । वहां अगस्त में इतना पानी बरसा है कि फ़सल चौपट हो गई है । पिछले वर्ष भी वह ज़िला सूखे और बाढ़ से वर्बाद हुआ और इस वर्ष भी। पिछले वर्ष ज़िले भर में 35 आदमी मरे, 60 हज़ार घर गिर गये । और 29 करोड़ रुपये की तबाही हुई । इस बरस भी ऐसे ही फ़िगर्ज़ होंगे । करीब तीस लाख लोगों की आबादी बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गई है । यह कहा नहीं जा सकता है कि उन का गुज़ारा किस तरह होगा । यू० पी० सरकार की भी आंख देवरिया की तरफ कुछ कम हो गई है ।

मैं श्री पन्त, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद और अपने नौजवान भाई, कृषि मंत्री, से कहना चाहता हूं कि मेरे बदले में वे वहां जायें और वहां के लोगों को सहारा दें । आज जिस विपत्ति में वे हैं, उतनी विपत्ति में वे पहले कभी नहीं थे । लेकिन ऐसी विपत्ति में सहारा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वे लोग 14 शूगर फ़ैक्टरियों

में चीनी पैदा करते हैं और एक्साइज ड्यूटी और परचेज टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये सरकार को देते हैं। लेकिन आज हमारी अवस्था ऐसी हो गई है, जिसमें हम को विशेष प्रकार से सहायता की जरूरत है।

मैं आज दिन भर इस सदन में बैठा रहा। आप के आने पर मुझे मौका मिला है और मैं अपने यहां के लोगों की बात सुना दी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, इस सरकार की पिछले सताईस वर्षों की गलत और जन-विरोधी नीतियों का ही यह फल है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में हर वर्ष कहीं सूखे और कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इस वर्ष भी उसी तरह की स्थिति हमारे देश के विभिन्न राज्यों में है, जिस की चर्चा हम आज सवेरे से कर रहे हैं।

हमारे सूबे बिहार में, खासकर उत्तर बिहार में, इस साल जैसी बाढ़ आई है, लोगों का कहना है कि वैसी बाढ़ पिछले बीस वर्षों में नहीं आई थी। इस बाढ़ के कारण जन-धन की जो बर्बादी हुई है, उस के बारे में बिहार सरकार ने एक टिप्पणी भेजी है। यद्यपि उस टिप्पणी में स्थिति की गम्भीरता को कम कर के दिखाया गया है, फिर भी बिहार सरकार ने जो कहा है, मैं उस का एक अंश पढ़ देना चाहता हूं :

"जहां तक विभिन्न जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, उस के अनुसार उत्तरी बिहार के 15 जिलों में से 14 जिलों में बाढ़ का प्रकोप हुआ। इन 14 जिलों का क्षेत्रफल 52,993 वर्ग किलोमीटर है, जिस में बाढ़ का प्रकोप 14,057 वर्ग किलोमीटर में हुआ। इन समूचे 14 जिलों की जनसंख्या 2 करोड़ 52 लाख है, जिस में से बाढ़ से पीड़ित जनसंख्या 69 लाख 77 हजार है। बाढ़ के प्रकोप के कारण 15,54,000 एकड़ में फ़सलों को नुकसान हुआ है। इस का अनुमानतः मूल्य 70 करोड़ 87 लाख रूपया है। अभी तक जो प्रतिवेदन उपलब्ध हैं, उस के अनुसार 1,03,542 घरों को नुक्सान होने की सूचना है और उन के क्षति का मूल्यांकन 3 करोड़ 62 लाख रुपया किया गया है, किन्तु यह अनुमान अभी प्रारम्भिक है और समय बीतने के बाद ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मकान की क्षति का सही अंदाज लगाया जा सकता है।"

सभापति जी, जब पांडेय जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि दोबारा तिबारा भी बाढ़ का प्रकोप चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि एक अरब से ज्यादा क्षति की तो बिहार को जरूर हुई होगी। बहुत सारे पशु धन की बरबादी भी हुई है और सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। लेकिन गैर-सरकारी सूत्रों का कहना है कि मरने वालों की संख्या कम से कम 30 जरूर है। इस तरह की स्थिति हमारे सूबे बिहार की और उत्तर बिहार की है। उत्तर बिहार का केवल एक जिला सिवान का है जो बाढ़ के प्रकोप से बाकी बचा है, बाकी तमाम जगह बाढ़ लोगों को तबाह किए हुए है। लेकिन सहायता नगण्य है। वहां की सरकार ने मांग की 35 हजार टन खाद्यान्न की और वह भी एक बार नहीं, हर महीने देने के लिए। लेकिन, ये वह भी नहीं दे पाते हैं, जब कि 35 हजार टन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अभी पिछले दिनों आधे घन्टे की एक बहस का उत्तर देते हुए खाद्य राज्य मंत्री ने कहा था कि हम आगे आने वाले महीनों में, तीन-चार महीने जो संकट के हैं, उनमें 70—80 हजार टन देंगे। मगर वह यह 35 हजार टन भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद् की बैठक ने, जो पटना में 13 से 15 अगस्त तक हुई,

[श्री रामावतार शास्त्री]

तमाम स्थितियों पर विचार करने के बाद मांग की है कि कम से कम एक लाख टन गल्ला आगे आने वाले संकट के महीनों में प्रतिमाह देने की व्यवस्था कीजिये और कम से कम 50 करोड़ रुपया दीजिये तभी आप सहायता कार्य जो वहां करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, अनाज, कपड़ा, दवा, मकान छप्पर जोर्न: जो भी जरूरत पड़ती है वह वहां दे सकते हैं। यह मांग हम लोगों ने की है। यह तो सहायता बाढ़ पीड़ितों के लिए चाहिए। बाढ़ के बारे में एक बात और कह दूं कि इसमें भूख से भी मौतें हो रही हैं। अभी बिहार राज्य के कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री श्री जगन्नाथ सरकार ने बाढ़-पीड़ित जगहों में घूमने के बाद यह बयान दिया है कि दरभंगा जिले में कुछ लोग भूख से मरे हैं। बाढ़ में बह गये वह तो अलग हैं, कुछ लोग इसके कारण भूख से भी मरे हैं और कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं।

दूसरी तरफ छोटा नागपुर के इलाके में, सिंहभूमि में, रांची जिले में, पलामू जिले में, संथाल परगना के जिले में, इन क्षेत्रों में सुखाड़ है। वहां भी लोगों के भूख से मरने की खबर मिली हैं। सात आठ व्यक्ति मर चुके हैं।

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : हजारी बाग जिले को भूल गये। उसे भी शामिल कर लीजिये।

श्री रामावतार शास्त्री : वह आप बोलिएगा तो कह दीजिएगा। हजारी बाग भी उसमें शामिल है। तो एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सुखाड़ और एक तीसरी बात भी है। बहुत सारे जिलों में और खास तौर से पटना जिले से मैं आता हूं, पटना की बात और नालन्दा की बात मैं जानता हूं कि किसी किसी इलाके में अतिवृष्टि के कारण मकई की फसल 50 प्रतिशत बरबाद हो गई। अभी तक हमारे यहां मनेर और दानापुर में बाढ़ ज्यादा नहीं आई है लेकिन गंगा नदी के बढ़ने से खतरा है। वहां की भी मकई की फसल और जहां जहां भी मकई की फसल है ज्यादा बारिश होने की वजह से वह बरबाद हो गई। तो उनकी भी मदद करनी होगी। सुखाड़ पीड़ितों की मदद करनी होगी, बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी होगी और पूरे बिहार को आप को खिलाना होगा। हम जानते हैं कि उन क्षेत्रों को बिहार की सरकार अकाल क्षेत्र नहीं घोषित कर सकती। लेकिन फि भी आप की जवाबदेही है उन्हें खिलाने की, कपड़ा देने की और उन्हें बसाने की।

इसके बाद कटाव के बारे में कहना चाहता हूं। कटाव की बात आप सुन ही चुके हैं मानसी के बारे में। इसके अलावा पूरे बिहार में जहां बाढ़ आती है या जहां नदियों के किनारे गांव बसे हुए हैं दियारे के क्षेत्र में हैं वहां लाखों किसान कटाव से पीड़ित हो रहे हैं। स्वयं मेरे क्षेत्र मनेर के दर्जनों गांव वर्षों पहले कट चुके और कुछ आज भी कट रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। तो इस तरह की समस्या कटाव की है उससे भी लोगों को बचाना है।

सहायता कार्य जो सरकार कर रही है वह असंतोषजनक है, उसको संतोषजनक बनाने की जरूरत है। लेकिन तमाम हिन्दुस्तान के हर कोने में चाहे बाढ़ आये, सुखाड़ हो, अति-वृष्टि हो, उससे लाखों कर्मचारी चाहे वे केन्द्रीय सरकार के हों, चाहे राज्य सरकारों के हों, पीड़ित हैं। जब जब भी ऐसी बाढ़ या सुखाड़ की स्थिति आई है सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को बाढ़ का भत्ता दिया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा पंत जी से कि वे वित्त मंत्री से बात करके सरकारी कर्मचारियों को जो बाढ़ अथवा सुखाड़ के इलाके के हैं, उनको बाढ़ का भत्ता दिलवाने की कोशिश कीजिये ताकि वे अपने परिवार को बचा सकें इस संकट की घड़ी में।

आखिर एक बात मैं नहीं कहता लेकिन बान सागर की चर्चा उठाई गई। मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो बान सागर से जो फायदा हुआ उसकी चर्चा उन्होंने की। उनको फायदा हुआ है उससे हम को जलन नहीं है, अच्छा है, हम खुश हैं कि उनको फायदा हुआ है। देश का वह भी हिस्सा है। लेकिन बिहार को जो नुकसान हुआ है खास तौर से जो सोन के इलाके के लोग हैं, मुझे शंका है और शंका क्या यह वास्तविकता है कि लाखों लोग उजड़ जायेंगे, उन्हे जो अभी पानी मिलता है सिचाई के लिए वह पानी नहीं मिलेगा। इसलिए जो इसके लिए समझौता किया गया है, वह वहां की जनता की मर्जी के खिलाफ है। उस समझौते का उस क्षेत्र के विधायकों, संसद सदस्यों और तमाम लोगों ने विरोध किया है। उन लोगों ने कहा कि यह समझौता मत कीजिये। ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिसमें उनको भी फायदा हो और हमारे राज्य को भी फायदा हो या कम से कम नुकसान न हो, लेकिन बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दिया। डा० के० एल० राव साहब भी मौजूद हैं और पंत जी भी मौजूद हैं, इनके मंत्रालय ने जो समझौता किया है उस समझौते से बिहार के और खास तौर से सोन के इलाके के लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : बिहार के लिए हम ने दस्तखत नहीं किये।

श्री रामावतार शास्त्री : आप ने नहीं किये हैं पर आपकी मौजूदगी में और आपकी रजामंदी से यह समझौता हुआ है। उसकी वजह से लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बान-सागर के बारे में फिर से विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि सरकार पूरी मदद बिहार की 70 लाख जनता को करे ताकि वहां कोई भूख से न मरने पावे और जो दक्षिण पंथी शक्तियां हैं जो गलत तरीके से आन्दोलन कर रही हैं उनको मौका नहीं मिले बिहार की 5–6 करोड़ जनता को गलत रास्ते पर ले जाने का।

MR. CHAIRMAN: We are now close to 6 P.M. There are still many members to speak.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I have consulted our members as well as Leaders of the Opposition and the Minister. I suggest that we sit till 7 P. M. today since there are a large members who want to participate. Since still there will be a large number of members left to speak, the debate will not conclude today; we will continue it on another day which we will decide later. But today we may sit till 7 P. M.

MR. CHAIRMAN: Is that the pleasure of the House? Some hon. Members: Yes.

MR. CHAIRMAN: We will sit till 7 P. M.

DR. MAHIPATRAY MEHTA (Kutch): I am thankful to Shri Shinde for expressing his sympathy for the people of Kutch which for four consecutive years has been suffering from drought. But let not this sympathy remain only in words, It should be translated into action.

Shri Maurya has taken care to settle the issue with a neighbouring State as far as grass is concerned. Shri Qureshi is not here. But I would like to request him through you to see that the railways carry the grass over there.

As far as Gujarat is concerned. we have both problems, floods and drought. But fortunately, the remedy is only one. If that is adopted, floods as well as drought can be tackled. That lies in the Narmada. On the south of Narmada, generally there are always floods. On the north side, gradually as you go, there is always drought. So far as Narmada is concerned, there

[Dr. Mahipatray Mehta]

is the Navagam dam project. I know the issue is with the tribunal. So I do not want to say anything about it. But I would make one request to Government through you. Today there is President's rule in Gujarat. When the decision is taken, it will take ten more years to be completed. But, Sir, when there is drought in so many districts over there, why should we not start digging of the canal so that more time may not be wasted and people may not have to suffer.

18.00 hrs.

The main reason why so many Members are inquisitive and they are taking part in this debate is because Government have recently accepted the recommendations of the Sixth Finance Commission. This is the main reason. There is fear about it and there is anxiety about it. People who are suffering and who have been affected by drought and floods worry about it; people fear that there would not be any sufficient relief this year. This is the main reason. Sir, in the report of the Sixth Finance Commission, it has been said that money has been misused. I would ask the Government, who has misused the money? It is the State Government over there; it is the fault of the State Government. If they cannot plan properly; if they cannot manage properly, why should the people be punished? Here is something fundamentally wrong. By accepting the recommendations of the Sixth Finance Commission, Government is going to punish the people, those who are already under misery. On the contrary, they should have seen to it that the money that was allotted, had been properly utilised. Therefore. I suggest that meaningful and purposeful relief work should be started immediately here in Gujarat. Here, I would say Narmada canal is the first thing which should be taken up and completed. You should start this immediately, just now, so that people may get relief. Sir, a figure was given in the Press that 90,000 people are engaged in relief work in Gujarat. But, I can tell you, in Kutch, there are 1,30,000 people. Famine has been a continuing feature; it is not that it has newly developed. In the district of Kutch, there are 35,000 people according to Government and in the whole of Gujarat 90,000 people are engaged in relief work; do you call this relief? Sir, in these areas, famine has not been declared; scarcity has not been declared. Famine has been continuing in Kutch in three or four talukas. In nearly 638 villages, relief work goes on and nowhere else. You can imagine their sad plight. Here, I must agree that in 1971-72 and in 1972-73, there was some nicely arranged relief work. But, I will have to support Shri P. M. Mehta, even though he is in opposition. There is no planning in this rule. These bureaucrats never care for the people. There is no actual planning by giving relief to the people. Let me tell you, what happened last year. Sir, it is a fundamental rule of the Famine Code that where there is less than 5 inches rains, scarcity should be declared. But, unfortunately, the officers who were ordered to go there, declared more than 4 annas, 6 annas and all the relief work, all the DPAP work was stopped in that area, resulting in tremendous hardship to the people. You can just imagine the condition of the people. When there is continuous famine; continuous drought, the economic condition of the people deteriorates. At the top of it, Government sits over it to save money and they give different arguments. It has happened this time also. Where is the question of waiting now? Let us say, it rains in Gujarat now. Will it be useful for the purpose? Will it yield any crops? Why don't we declare scarcity just now? In all these areas, in Sourashtra, in Navnagar, Jamnagar, Amreli, Bhavnagar etc., scarcity should be declared. Drought has been continuing; famine has been continuing for the three years. But, the authorities are going against the fundamental rules of the Famine Code, which is the oldest one; it is as old as

the British Rule. We do not catch up with the very spirit of the rules. Last time, when we fixed Rs. 3 as the minimum wage, we were taking pride of it. But, I would ask the Government, taking into account the price rise and the rules of the Famine Code, whether the people are supplied grains in actual quantity and not the money part of it? Today, in paper, they are getting Rs. 3, nobody is getting Rs. 3. But, is it possible for a person to maintain himself in Rs. 3? I would ask this question and I would ask Mr. Pant, to ask this question himself, in his heart of hearts.

Actually it is the value of the grains that should be paid. If they work for 7 days, they are marked absent for two days and paid only Rs. 15. I request that this amount of Rs. 3 should be increased to Rs. 5 which should be the minimum. If there is so much economic crisis, I suggest that the minimum should be Rs. 3 but if they put in more work, they should be paid Rs. 5.

Immediately without waiting for a day, I request the hon. Minister to declare scarcity in Saurashtra and Kutch area. It is the President's rule. The officers are waiting for order from you. Tomorrow it should be declared scarcity area. If it is not declared scarcity area, even grass is not supplied. In my district, a minimum of 3000 cattle are dying daily and cattle from the backbone of the economy of the area. Before partition, people from that area used to cross over to Lower Succar Barraz in Sind. Essential commodities like wheat used to come from Sind and in exchange, we used to give brassware silverware, *a jrak*, etc. After partition, the economy of these artisans has been completely ruined. They cannot go to Sind and they are not provided with any alternative. Have you ever thought of the impact of the famine on this area after partition? You have thought of giving aid to every refugee from Pakistan. But here is a part of our land which is totally ruined. If I give a complete picture, tears will come. The people there are living in such miserable conditions, with only

skins and bones. Today people are developing night blindness. Mr. Tiwary said that famine is better than flood. I am prepared to exchange my constituency with anybody. Let them come and see the pangs and miseries and the pitiable conditions of the people there. They do not even get a drop of drinking water. We are talking of DPAP. All the green trees have been chopped off and the charcoal has been manufactured and exported to Dubai. Not a single tree is there in Kutch. The result is there is coal shortage and even kerosene is not available in the market. For the fault of the Government servants, the poor labourers are punished. They have no alternative fuel. Do you think DPAP can be implemented like this?

To whom are they accountable? In this context I sppport Shri Vasant Sathe who rightly said that people from the public should be associated with that.

This is a very serious problem and it cannot be solved by bureaucratic rule. Only a popular rule could appreciate the urges and feelings of the people. There was an officer who said that the solution of the cattle problem in Kutch is to destroy all the cattle! This is adding insult to injury. That officer was saying that "every year you are having drought; so, what is the harm if you destroy all the cattle". So, this is the attitude of the officials.

Le me tell you that the patience of the people has exhausted. It has reached the breaking point. The blood of the poor people is turning into tears. When their blood dries up and they do not have tear in their eyes, then their eyes will get red. Let me warn the Minister and the Government that it will mean the *Trilochan* of Shiva.

We do not want violence in India. At the same time, we are nourishing violent. Suppose somebody has become an opportunity to everyone to become violent. Suppose somebody has caught hold of my throat. I have to slay him to save myself. If the Government do

[Dr. Mahipatray Mehta]

not hear the grievances of the people and remedy them, if they pay only lip sympathy naturally the people will become violent.

The two basic principles of life are propagation of life and protection of life. They are the basic principles of life the whole world. So, I would request the Government to pay attention to the protection of life.

I know that the Minister belongs to Uttar Pradesh. Shri Bibuthi Mishra was saying that Pantji has not gone to Bihar. I would request the Ministers, any Minister, to visit my area and see the plight of the people there. Now that President's Rule is there the responsibility on the Centre is great. As Shri Satarwala, the Adviser to the Governor, has said "when I see the pitiable condition of the people, tears come to my eyes; but I am an officer; I cannot do much."

He can give only sympathy and tears because of the rigidity of the rules and regulations. I hope something will be done to ameliorate the condition of the people.

MR. CHAIRMAN: I am sure he will go to Gujarat.

SHRI NIMBALKAR (Kolhapur): Mr. Chairman, today's subject revolves round two aspects; one is giving immediate relief to those suffering from drought and floods; the other is the short-term and long-term measures that must be taken progressively, gradually and ultimately to completely overcome those areas which are flood-prone and drought-prone.

When I was just hearing the speaker before me, I asked myself whether it is right for me to get up and speak if the matter is to be considered only constituency-wise. But the way I look at this problem, I think it is very essential that even I should rise at this time, even though my constituency is not affected by floods and is, really speaking, seldom affected even by droughts. *(Interruptions)* The point is this. If you start trying to milk a cow which does not have milk, then you should not blame others when they are not going to give you an opportunity to milk a cow though it has milk.

It is my contention that when you are going to develop 72 districts in this country which are drought-prone, the question that comes before you, in most of the districts, is as to wherefrom you are going to get water to develop these districts? One is that you can get water from underground if there is enough water underground and the other is that water has to come through flow from somewhere else where there is rain. My constituency happens to be such a place where it rains. Right from my constituency, that is, from southern Maharashtra onwards, most of the northern belt of Karnataka and major part of Andhra Pradesh, all these areas, if they are to get water, you cannot develop these areas without water. Therefore, you have to milch the cow where there is milk.

This is what I have been trying to tell the Government for the last three years. I can assure you that the whole of the area that I have just mentioned could be turned into another Punjab, another granary of India if those dams which are to be built in Kolhapur district and which have been sanctioned by the Central Government, are completed. I cannot understand how it is that this Government or any State Government or even the Maharashtra Government cannot realise that after the Himalayas, the area which has the most amount of water is the *Sahyandris*, the Western Ghats. It is true that the Planning Commission has formed a committee for Western Ghats. It is under the Chairmanship of the Chief Minister of Maharashtra also. But unless you create a situation in the *Sahyandris*, the Western Ghats, where you can really take all the water that is there

and use it for irrigation purposes, you will not succeed in solving the food problem of this country. The whole of the Deccan Plateau can be turned into a granary provided you develop the Western Ghats, the *Sahyandris*, as they are known here. There is so much of water here. If you can make use of all the water and not let it run down on the Konkon side into the sea, the whole of the Deccan Plateau can be converted into a granary for India.

For instance, there is one dam, Radhanagri dam, built by the Shahu Chhatrapati of Kolhapur who had the imagination to understand this and who built that dam in the twenties or thirties. That dam has given Kolhapur the largest jaggary market in the world. Just one dam has done it. These things are not realised. In this country, we have got so many resources. We do not seem to have the will; we do not seem to have imagination. I cannot understand it.

My hon. friend, Shri Siddheshwar Prasad who is here now has come to Kolhapur. Unfortunately, he stayed there not long enough. But if he had given me a chance to show him round, I can assure you that it would not have been difficult for me to convince anybody for that matter that this is the sort of areas you have to develop, not for the benefit of the area itself but for the benefit of other areas also. If you build a dam, for instance, some land behind the dam is taken away from the people. That is also a sacrifice. But here is a case where it is in your hands to develop this area and save this country from starvation. And you just do not do it. I cannot understand that. I think, I have had the luck and I have tried to convince the Planning Commission and the Minister to have a next meeting in Kolhapur so that I can show them all these things. These things must be looked into.

I can forgive a Minister; I can forgive a Government for not doing something because doing something, in fact, is also not to bring about anything. In this particular case, I can say that the whole of the Western Ghats area needs development in a correct way. If you are going to do that, you are going to have the vast granary that you can think of.

For example, if you take sugarcane, one Zila in Kolhapur, because of one dam, can house over 14 sugarcane factories. We have already got 7-8 sugar factories which is more than the sugar factories in any other district in the country.. (*Interruptions*) I do not know how much sugar they produce but the quantity of sugar that we produce should also be compared. Dr. Rao had been there. He knows what I am speaking about. He surveyed the entire area in a helicopter and he often told me, 'Why don't you get the dam'. So, I sincerely belive that my constituency is really speaking a key to the solution of the problems of this country and I offer my constituency as the price to solve this problem and my constituency will give you what you want and will really feed the people.

Another thing I have to say is: perhaps the biggest problem for the Minister is: wherefrom the money will come? At the present stage wherefrom the money will come? I have already told the Finance Minister to reimpose the kind of tax which I had suggested during the time the refugees came over from Bangla Desh....

MR. CHAIRMAN: You need not worry about the money. The Minister will find it.

SHRI NIMBALKAR: I am afraid this time they will find it unless they take extraordinary measures. Whether you like it or not, I can tell you now that all their promise of keeping the deficit finance pegged down to Rs. 126 crores will not be kept. You can believe me on this. And the most important thing for this Ministry is that we must sug-

[Shri Nimbal Kar]

gest new ways without hurting the poor people—this is very important—without hurting the poor people, to create resources, particularly, to get rid of the floods. I repeat again what I have said in this House before, that for every ear of corn that you lose on account of floods, you will have to go for two ears of corn somewhere-else and it is very difficult to do it. It is much easier to control or even eradicate floods. That is why I say again that the tax, the refugee tax—this time you may call it floods tax—should be reimposed unless all floods are completely controlled and eliminated and this tax should be for that purpose.

*SHRI M. K. KRISHNAN (Ponnani): Mr. Chairman, Sir, while taking part in this discussion I would like to draw the attention of the House to the problems in Kerala. Dr. K. L. Rao and other hon. Members have referred to those problems. The problem of Kerala is not flood alone. About 400 kilometres of the coast-line of Kerala have been attacked by sea-erosion. Dr. K. L. Rao referred to the valuable land that is being eaten away by the sea. Similarly, Shri Stephen has spoken about the mineral wealth of the sea shore. Kerala has been confronting this problem all these years but no solution has yet been found to this problem so far.

Now the floods have devastated Kerala. Not only that, Kerala has faced another big problem and that is landslides. As a result of landslides a number of distrists which produce cash crops that bring us foreign exchange have been destroyed. Idikki has an important hydro-electric project in our country. Therefore this Idikki District is very important. Similarly, Sir, Wayanad District is also important from the point of view of cash crops that earn foreign exchange for us. These districts have been badly affected by landslides.

It is not only that valuable cash crops have been damaged but thousands of people have also been affected. They have lost their homes. Six panchayats of Idikki District have been completely wiped out by landslides. About one and a half lakhs of people have been affected. About 50 people have lost their lives in Idikki alone. In Quilon 4 people died and in Cannanore two people have lost their lives and in Kozhikode 12. Many people have sustained injuries.

Sir, Kerala is facing a very serioous crisis due to landslides and other natural calamities. The people there are facing great misery. The Government of Kerala has announced only Rs. 1 lakh for a district for relief work. When 1½ lakhs of people are facing difficulty in an important District like Idikki and the State Government have announced only Rs. 1 lakh for relief measures you can imagine that even one rupee will not be available for one man. The State Government has drawn the attention of the Central Government to this matter. I do not want to go into the details, but according to preliminary reports available so far, the total loss estimated is about Rs. 6 crores.

In the matter of food, Sir, Kerala is a deficit State and it has always to look to the aid of the Central Government. Kuttanad is the rice bowl of Kerala. About one lakh acres of paddy fields have been destroyed by floods and crops damaged. Hon. Members who participated in the discussion said that rice is selling at Rs. 3/- a kilogram and they were agitated over it. I have to inform the House that one kilogram of rice is selling at Rs. 7/- in Kerala. At Trivandrum, which is the capital of Kerala, I got one kilogram of rice

*The original speech was delivered in Malayalam.

for Rs. 5.25. When the price of rice is Rs. 5.25 a kilogram in Trivandrum you can imagine what the price will be when it reaches Cannanore. Because of the floods one lakh acres of paddy fields of the rice bowl of Kerala have been damaged. The entire crop of paddy has been destroyed. You can imagine what the fate of the people there will be during the days to come.

Sir, Kerala, as I said, is a deficit State. Almost all districts of Kerala are affected by floods and the people are in utter misery. The situation is such that this misery will increase in the near future. The State Government and the Central Government will have to consider this problem very seriously. Then only this situation can be tackled. The aid that the Central Government has announced is only Rs. 1 crore and that too as loan. The State owes Rs. 30 crores to the Central Government by overdrafts. The Central Government has now given only Rs. 1 crore by way of ways and means advance. Is it the way to help the people? You have not given this amount as aid or as assistance the people; this has been given as a loan of ways and means advance.

Kerala deserves better help from the Central Government especially when our State is bringing foreign exchange to the tune of Rs. 125 crores from cash crops only. It is the responsibility of the Central Government to help the people whose cash crops have been damaged by floods and landslides. You have to give serious consideration to this matter. Cent per cent relief and compensation should be given to the people affected by floods, landslides and sea-erosion and that is to be met wholly by the Centre.

Anti sea-erosion measures will have to be taken on a big way. It was started but not completed. The State Government is not in a position to complete it. Therefore the entire work has been stopped. The Central Government has a responsibility to save the State in order to protect the valuable mineral resources.

So far as Kerala is concerned, although it is a small strip of land, there are 44 rivers in that State. During the rainy season there is misery throughout the State because of floods. These rivers if they are properly harnessed they can change the complexion of the State. The Communist Government which came to power in 1957 had prepared a Master Plan to harness these 44 rivers and use these rivers for the progress and prosperity of the State. In 1958 they submitted the scheme before the Central Government. But it has been put in cold storage and dust has accumulated on the files. If that plan had been implemented certainly Kerala could have been saved from the present miserable situation and we would have been in a position to prevent the floods there. I hope the Government would think about it and formulate certain schemes to implement that Master Plan. That is all what I have to submit.

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj): Mr. Chairman, Sir, first of all, let me be permitted to quote from the report submitted by Shri G. L. Nanda, Minister of Planning and Irrigation and Power on Flood situation and the flood control programme in the year 1956. This is what he said:—

"The State Government consider that the detention reservoirs may be constructed on the river Rapti at a cost of Rs. 15 crores. Provision of such reservoirs has been made by the State in their proposals for inclusion in the Second Five Year Plan. Thirteen small detention reservoirs on the tributaries of the Rapti are also proposed to be constructed at a total cost of Rs. 4.6 crores. These proposals are under the consideration of the State and the Central Governments.

[Prof. S. L. Saksena]

"A scheme has also been prepared for the construction of a multi-purpose dam on the Rapti at Jalkundi in Nepal. Besides controlling floods, the reservoir wiil be able to generate 27,000 k.w. of power and helps to irrigate 4.5 lakhs of acres of land in U.P. and Nepal. According to funds available for flood control work during 1956-57, the probable allocation to U.P. will be Rs. 1.5 crores which will form part of the Second Plan programme. A tentative alllocation of funds to the State for flood control schemes in the Second Plan is Rs. 10 crores. Details of the schemes are being worked out."

This was in the year 1956. Since then 28 years have passed. I am sorry to say that not a single measure has been taken up and implemented although it was promised at that time. The result is that we have been seeing the recurring floods in Gorakhpur and Basti Districts. There were droughts and floods. In the month of June and upto 10th of July there was drought this year. Then came the floods the like of which we never had during the last one hundred years. I have been in this constituency for the last forty-five years or so and I can tell you that I have never seen such a devastating flood as this year. I toured this flooded are for ten days during the last month and I found that in many villages people there have lost everything. Flood waters entered their houses and they lost everything they had in them. They lost all their crops completely. Some human lives have also been lost and many cattle have been washed away. I am very sorry to say that none had been alerted. If this had been done, the people would have been prepared. Nobody went to their help. InGorakhpur we never saw such a situation. Last time, the flood level was the highest 50 years back in 1925 when its level stood at 251.15 feet. But, this time it became 252.52 feet—about 1½ feet higher. Therefore, my request to you Is this. My Chief Minister has asked for Rs. 100 crores from Central Government for flood relief immediately. If the Central Government does not give this money for flood relief immediately to the U.P. Government for help to people affected by floods, there would be starvation deaths. I have seen myself the conditions—miserable conditions—of the people. Unless they are helped at this time, many will die of starvation. I have seen people going without food for days. If this thing continues, there would be large numbers of deaths. You must give them all help. You cannot keep people alive for ever by doling out charity. Utilise their manpower for constructing *bunds* to save the people from flood ravage and to provide them with work.

The people will have no crops in the next nine months. The rabi crop will come in April next. You must give them work during these 8 months and it will be possible if you start repairing bunds, roads and start raising villages immediately otherwise there will be starvation deaths on large-scale. About 1000 villages have got marooned and there is water all alround and these villages have to be raised. They are all very low and water entrers in the houses during floods. Unless you raise these villages they will be flooded again and they will again lose their all in addition to corps. Therefore, the most urgent thing is that you must give them work on the repair of bunds, roads and raising of villages immediately. Further, you will have to give them rabi seeds in time for sowing rabi crop. Every year it comes after the sowing season is over.

The cattle are starving. Fodder has to be rushed and forests have to be thrown open for grazing. Something is being done by the District Magistrate who is doing all he can but he has no funds. The U.P. Government has no money to spare for flood relief work. The Chief Minister of U.P. has requested the Central Government for Rs. 100 crores to help him in relieving the flood distress. So, I request the Central Government to give Rs. 100

crores to the U.P. Government to meet this situation. Centre must also take up the Jalkundi scheme immediately which was formulated in 1956, and must construct the reservoirs envisaged on Rapti and its tributaries.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : 28 बरस के बाद भी हम देश को प्राकृतिक विपदाओं से बचाने का प्रबन्ध नहीं कर सके। बाढ़, कटान, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि से देश के बहुत बड़े भूभाग प्रतिवर्ष भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं। कुछ भागों के या प्रदेशों के पिछड़े रह जाने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक देश के ये भूभाग पिछड़े रह जाएंगे हम गल्ले के मामले में आत्म निर्भर नहीं बन सकेंगे, जब तक इन विपदाओं से इन भूभागों को हम बचाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, आत्म निर्भरता के अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसका एक मात्र उपाय के अपने लक्ष्य को हम प्राप्त यह है कि यह विषय सैंटर का होना चाहिये, राज्य सरकारों का नहीं। राज्य सरकारों के पास टैक्नीकल नो हऊ नहीं है, पैसा नहीं है, इस समस्या का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। आप देखें कि गंगा नदी या कोई भी दूसरी नदी देश के कितने ही भागों में हो कर बहती है और हर प्रदेश अपने इलाके को बचाने के लिए अपने ही तरीके से बांध आदि बना लेता है और उससे झगड़े खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर बक्सर कोइलर—बांध बनाया जा रहा है जोकि बलिया जनपद के दाहिने हाथ पर पड़ता है और इसका बलिया पर बहुत ही बुरा असर पड़ने जा रहा है, बलिया डूबने जा रहा है। केन्द्र के हाथ में यह विषय होता तो एक समन्वित योजना वह बनाता और सभी इलाकों के हितों का ध्यान रखता। जो समन्वय होना चाहिये मौजूदा व्यवस्था में वह नहीं हो पा रहा है। इस वास्ते जब तक यह सारा विषय सैंटर का नहीं होगा तब तक ये झगड़े भी चलते रहेंगे और कुछ इलाके बुरी तरह से प्रभावित भी होते रहेंगे और साथ ही साथ वे पिछड़े हुए भी रह जाएंगे और सारी चीज बिगड़ जाएगी। इस वास्ते इस पर आप विशेष ध्यान दें।

योजना मंत्रालय ने भी इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया है। राहत कार्यों पर हर साल काफी पैसा खर्च किया जाता है। तकावी लोन आदि दिए जाते हैं। लेकिन यह समस्या का स्थायी हल नहीं है। हमारे देश में साठ सत्तर प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं या एक डेढ़ बीघा के मालिक हैं। अब ऐसे समय में जो तकावी आदि दी जाती है या डिसट्रैस लोन आदि दिए जाते हैं वे पटवारी लोग सवर्णों के दबाव में आ कर उनको ही दे देते हैं, उन्हीं को पैसा मिल जाता है. दूसरों को भी जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे भी उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता है। आपको चाहिये था कि इस पर आप गम्भीरता से सोचते और जो राशि आप राहत कार्यों पर खर्च करते हैं उस पैसे से या थोड़ा बहुत किसानों से और लेकर आप उनकी फसलों का, मवेशियों का मकानों का बीमा कर देते। इससे उनको काफी राहत मिल सकती थी। यह प्रोडक्टिव काम होता। इसके लिए आप टैक्स भी लगा सकते थे। और भी किसी तरह से इस काम के लिए अगर आपको पैसा चाहिये था तो वह आपको मिल सकता था, कोई नुक्सान वाली बात नहीं है। देश पैसा आपको दे सकता था। अगर देश को आत्म निर्भर बनाना है, तो इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन उस के साथ बड़ा अन्याय किया गया है और उस को उपेक्षित और पिछड़ा रखा गया है। तीन चार विषमता वाले क्षेत्र उस में हैं। उस की आबादी और आकार सब से बड़ा है। बैंकों, फाइनेंस कमीशन और अन्य फिनांशल इस्टीट्यूशन्ज में हमारे प्रदेश का जो पैसा लगा हुआ है, अगर वही हमें उपलब्ध कर दिया गया होता, तो आज हमारी यह स्थिति न होती। सरकार और प्लानिंग कमीशन ने हमारे प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया है।

श्री चन्द्रीका प्रसाद (बलिया)

अब मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हू । गंगा नदी गायघाट के पास बलिया-बेरिया तटबंध को काट रही थी । अगर यह तटबंध कट जाता, तो पूरा ज़िला समाप्त हो जाता । स्टेट के इंजीनियरों की राय थी कि इस तटबंध को छोड़ कर एक दूसरा बांध पीछे हट कर बनाया जाये । डा० के० एल० राव वहां गये थे । उन्होंने कहा कि हम गंगा को यहीं पर रोकेंगे । उन्होंने वहां स्थायीस्पर बनाने का सुझाव दिया, जिस से वह तटबन्ध बच गया है और बलिया जिला सुरक्षित है ।

चक्की चांद देरा, चांदपुर, बलवा और महाराजगंज को घाघरा काट रही है । इसके कटने से घाघरा अपना रास्ता बदल देगी, जिस से सम्पूर्ण ज़िला समाप्त हो जायेगा, विशेषकर दोआवा क्षेत्र घाघरा में विलीन हो जायेगा मैंने इस बारे में श्री पन्त और फ्लड कमीशन को पत्र लिखे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई स्कीम नहीं बनाई है । आप को पता होगा कि बलिया शहर तीन बार गंगा में विलीन हो चुका है । यह चौथा बलिया है । यह भी कट रहा था, लेकिन स्थायी स्पर बनाने से वह बच गया है ।

मैं कोई इंजीनियर या विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि घाघरा के कटाव को रोकने के लिए स्थायी स्पर बनाये जाने चाहियें । फ्लड कमीशन को इस बारे में जांच करनी चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए । बलिया में जो दो फ्लड डिविजन है, वे गंगा फ्लड कमीशन पटना की राय से यह योजना बनायें । इस काम पर पैसा जरूर लगेगा, लेकिन जनता पैसा देने के लिए तैयार है । यदि आवश्यक हो, तो फ्लड के लिए टैक्स लगाया जा सकता है ।

त्रिवेदी आयोग के अनुसार बिहार के अस्सी गांव बलिया, यू० पी० में आए हैं । उन में मुख्य गांव मुझाव छपरा, शिवपुर नौरंगा, जम्ही का दियारा, उमरपुर दियारा इत्यादि हैं । इस के आलावा शिवपुर दिय पहले से बलिया में है। ये गांव गंगा की मुख्य धारा में पड़ते हैं । बक्सर-कोइलवर बांध के बनने से ये गांव डूब जायेंगे । इन गांवों को बचाने के लिए फ्लड कमीशन ने कोई योजना नहीं बनाई है और इन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ के सम्बन्ध में जो सूचना दी है, उस के अनुसार जुलाई के अन्तिम सप्ताह से ले कर अगस्त के पहले पक्ष में बाढ़ से जो 9 ज़िले प्रभावित हुए, उन में प्रभावित ग्रामों की संख्या लगभग 7 हजार और प्रभावित जनसंख्या लगभग 26 लाख है। लगभग 19 लाख एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, जिस में से लगभग 13 लाख एकड़ कृषि क्षेत्रफल था और उस की फ़सल पूर्णतया नष्ट हो गई है ? इस के अतिरिक्त लगभग 63 हज़ार मकान क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुके हैं ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकारी कर्मचारियों को तीन महीने से तन्ख्वाह नहीं दे पाई हैं । मेरा सुझाव है कि छः सात महीने तक टेस्ट वर्क और क्रैश प्रोग्राम चला कर गरीबों और भूमिहीन मजदूरों को काम दिया जाये, ताकि इस भीषण महंगाई में वे अपनी जीविका चला सकें और उन की परचेजिंग पावर कायम रह सके । जिन लोगों के पास पैसा है, उन के लिए राशन की दुकानें खोली जायें । बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाये । गरीब किसानों को मुफ्त बीज दिये जाये । बी० एस० एफ० रेलवे और मिलिटरी आदि सैंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को तीन महीने की एडवांस तन्ख्वाह दी जाये ? इसकी भर्ती बालिगों के लिये खोली जाय ।

गंडक कैनाल को बलिया में लाकर अप्रैल, मई और जून में पानी दिया जाये। इस प्रकार

जुलाई में फसल कटने पर बाढ़ से कोई बर्बादी नहीं होगी।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश से मैं पहला ही सदस्य हूं, जिसको बोलने का मौका मिला है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अधिक समय देंगे।

सभापति महोदय : मुझे खेद है। आज यह सदन 7 बजे तक चलेगा। आपके बाद और दो सदस्यों को मौका देना है। इस लिए कृपया आप मेरी मदद करें।

श्री चंदू लाल चन्द्राकर : हमारे देश में कहीं भीषण बाढ़ है और कहीं भयंकर अकाल है। इन दोनों परिस्थितियों का सामना करने के लिए कई वर्षों से योजनाओं पर विचार होता रहा है। एक अन्तर्राष्ट्रीय टीम के आंकड़े हैं कि हमारे देश के 5,67,000 गांवों में से 80,000 गांवों में सिंचाई की व्यवस्था करना लगभग असम्भव है, जब कि शेष गांवों में नहर, लिफ्ट इरिगेशन, पम्प या ट्यूबवैल से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है।

इस लिए यह आवश्यक है कि तीन किस्म के निगम बनाये जायें। छोटी सिंचाई योजना के लिए छोटी सिंचाई निगम, मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए मध्यम सिंचाई निगम और बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बड़ी सिंचाई निगम बनाये जायें। देश में जितने पब्लिक फिनांशल इंस्टीट्यूशन्ज हैं, वे सब से अधिक पैसा सिंचाई योजनाओं में लगाये। मैं तो यहां तक सुझाव दूंगा कि जो लोग काला धन इन निगमों में लगायें, उनको रीबेट और अन्य सहूलियतें दी जायें, ताकि सिंचाई के लिए अधिक से अधिक पैसा आ सके।

उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, महाराष्ट्र और गुजरात आदि जितने धान पैदा करने वाले क्षेत्र हैं, उनमें काफ़ी अकाल है। मध्य प्रदेश का जो सब से अधिक चावल पैदा करने वाला क्षेत्र है—छत्तीसगढ़, वहां इस साल भयंकर अकाल है। वर्षा कुछ दिन पहले हुई है, लेकिन अब चाहे कितनी भी वर्षा हो, वहां पचास प्रतिशत से अधिक फ़सल नहीं हो सकती है। केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री ने यह मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार पचास हजार टन चावल केन्द्र के लिए दे। इस साल मध्य प्रदेश सरकार के पास भी चावल की बहुत कमी है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से किसी तरह भी चावल मिलना मुश्किल है, बल्कि मैं समझता हूं कि असम्भव है।

वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 30 हजार टन चावल की मांग की है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री इस बात की ओर ध्यान दें और मध्य प्रदेश को अधिक चावल देने की कृपा करें।

कुछ समय पहले केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री शिन्दे, रायपुर गये थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में. चावल पैदा करने वाले क्षेत्र में, उत्पादन बढ़ाने की बहुत क्षमता है, लेकिन अभी उसको पूरे साधन उपलब्ध नहीं किये गये हैं। वह ऐसा क्षेत्र है, जहां कम पैसे से सब से अधिक उत्पादन हो सकता है। इस लिए कृषि मंत्रालय की तरफ़ से 100 करोड़ रुपये की योजना बनाने की बात तय हुई थी।

केन्द्र की ओर से मध्य प्रदेश के लिए जितनी भी योजनायें बनाई जाती हैं, चाहे वह कापर का प्लांट हो और चाहे एलुमिनियम का प्लांट हो, वे सब पहले तो मेरिट और इकानोमिक प्रिंसिपल्ज के आधार पर स्वीकार कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में कुछ अन्य कारणों से वे सब योजनायें वहां से हटा ली जाती हैं। मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ के सम्बन्ध में यह सौ करोड़ रुपये की योजना भी इसी तरह समाप्त कर दी गई है।

इस वर्ष छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, जिसकी आबादी लगभग सवा करोड़ है, लगभग

[श्री चंदू लाल चन्द्राकर]

पचास लाख की आबादी के क्षेत्र अकाल से भयंकर रूप से पीड़ित हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उस क्षेत्र में दस लाख ऐसे परिवार हैं, जिनको दाल, चावल या गेहूं नहीं मिलता है, और जो पत्ते खा कर गुजारा करते हैं। जो कोदों होता है वह वे खा लेते हैं लेकिन उनको चावल या गेहूं नहीं मिलता है और उनके पास क्रय शक्ति नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार राहत कार्य के लिए इस इलाके को अधिक से अधिक पैसा दे और इस क्षेत्र में जैसे दुर्ग है, बिलासपुर है, यहां इस साल अधिक भयंकर अकाल है. बिलासपुर में तो कई सालों से लगातार अकाल पड़ता रहा है। कुछ वर्षों से और खास तौर से इस वर्ष बिलासपुर के न जाने कितने लोग--कुछ लोगों का अन्दाज है कि 50-60 हजार लोग बाहर और जिलों में काम ढूंढने के लिये चले गये हैं। इस साल मध्य प्रदेश में जितने भी चावल के क्षेत्र हैं वहां भयंकर अकाल है और ऐसे समय पर आवश्यक है कि जो वहां सिंचाई के बड़े बड़े साधन हैं--हसदो बांगो एक बहुत बड़ी सिंचाई की योजना है, वह लागू नहीं की जा रही है, मेरा निवेदन है कि उसे लागू किया जाय।

यह योजना 77 करोड़ की है। लेकिन इससे उस इलाके में न केवल बिजली पैदा होगी कम मूल्य पर, बल्कि साढ़े आठ लाख एकड़ में सिंचाई भी हो सकती है। इसी तरह से बस्तर में एक बहुत बड़ी योजना है जिसे बोधघाट-योजना कहते हैं। वह योजना जब बनी थी पांच साल पहले तो 37 करोड़ की योजना थी। अब वह मंहगाई के कारण लगभग 110 करोड़ की योजना हो गई है। इस तरह से सिंचाई और बिजली के वहां अच्छे साधन हैं। 45 प्रतिशत मध्य प्रदेश की बिजली की मांग को बोधघाट योजना पूरा कर सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसी ऐसी योजनाओं को अब तक मध्य प्रदेश में चालू नहीं करेंगे तब तक यह बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त विकास नहीं कर सकेगा। इसकी निरन्तर उपेक्षा अब तक होती रही है, इसकी हालत अच्छी नहीं हो सकेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इस वर्ष उस क्षेत्र में कम वर्षा हुई है। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत जो फसल बोने का प्रयत्न किया जा रहा है तो उसमें कीड़े अभी से लग रहे हैं। उसके लिए कीटाणु नाशक औषधियां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मांगी गई हैं। लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं अनुरोध करूंगा केन्द्रीय सरकार से कि वह कीटाणु नाशक औषधियों की व्यवस्था करे।

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): Mr. Chairman, Sir, I would like to say something on the alarming situation, especially the scarcity conditions, about which there is the Government report, which we have also received. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the scarcity conditions due to drought. The result is, ultimately, starvation conditions are emerging. This is Government report. But, according to my own report, from my own source, starvation deaths have already started. I need not give a detailed picture about that. But, with maximum and terrible type of floods in northern Orissa side by side with drought conditions in the southern District of Orissa, the situation has become quite alarming. The Prime Miniser has been apprised of the situation by the Chief Minister of Orissa. Therefore, I want that the hon. Minister should realise this aspect while thinking of any help or financial assistance for the State. Now, the question is, out of 15 districts, 13 districts have been affected. With regard to this drought situation and scarcity conditions, I have to make one suggestion.

Now, there is a reversal in Orissa Government's food policy. This has come out in today's *Patriot*, the Cabinet has taken a decision. I want that

the Central Government should intervene and see that procurement is not allowed to private agencies about which a decision has been taken yesterday. This should be put an end to and the policy which is going to be followed should be reversed; at least, the old policy should continue. Now, the hoarders who are taking advantage of these scarcity conditions, these rich kulaks and big landlords, they have all combined today and are taking the help of bureaucrats as well as police.

Wherever there is dehoarding compaign, they have started cases against them and indiscriminately started arresting them, as happened in Ganjam district. We should not allow a single person to die of starvation. That is possible only if the Centre gives proper assistance. As per the old prescription of the sixth Finance Commission, we are to get only Rs. 1.5 crores from the Centre and the State will have to give Rs. 1.5 crores. But the conditions are so alarming that we require a minimum of Rs. 20 crores That is what the State Government has demanded to save the starving people. Now even starvation deaths have started.

At least some multipurpose irrigation projects which has been promised long, long ago like Rengali project and Bhimkund project should be taken up and completed. For the last 17 years, in Ganjam district several projects have been taken up but the full money is not forthcoming and they are being postponed. These spill-over project have to be given preference and full amount should be allotted for completing them, so that the poorlandless people who are going to face death can be saved by giving them employment.

*SHRI M. M. JOSEPH (Peermade): Mr. Chairman, Sir, India has always been facing two problems—floods and drought. However much science has progressed so far we have not been able to prevent floods or drought. It is really unfortunate. This is a very very serious situation. Many States in our country are faced with floods and drought simultaneously. In Kerala, especially, we are faced with annual floods. This year we have been faced with heavy floods. My hon. friend Shri Krishnan has dealt with it.

Sir, Kerala is a very beautiful State. The entire complexion of the State has changed due to floods and landslides. Paddy fields have been completely damaged and submerged in water. The coastal area has been washed away by the sea. So far as Idikki is concerned there is no sign of such constituency. Things have changed very much in that area. Two months ago the hon. Minister Shri Pant visited Idikki and he was very much attracted by the beauty of nature there. Today if he goes there, Sir, he will be moved to tears seeing the miserable condition of the people of that area. Landslides and floods have taken the lives of many people there. Cash crops have been destroyed. Our State earns Rs. 125 crores of foreign exchange from cash crops. Today the position is much that the entire cash crops have been damaged.

I have read in the papers that Shri Pant is in favour of giving assistance for replanting the cash crops. Assistance should be given for replanting the cash crops. Short term and long-term measures will have to be taken to help the people. The Central Government has given only Rs. 1 crore and that too by way of ways and means advance. Our State is deficit in food. 80 per cent of the paddy fields of Kuttanad has been affected by floods. Therefore the Central Government should take special care to see that foodgrains are rushed to Kerala. Unless and until the Central Government gives financial assistance to Kerala the misery of the people there will increase.

Sir, we have been treated in a bad way. The figures show that in 1967-68 out of the total allotment of Rs. 8,000 lakhs Kerala got only Rs. 9 lakhs and in 1971-72 out of a total allotment of

*The original speech was delivered in Malayalam.

[Shri M. M. Joseph]

Rs. 21,000 lakhs Kerala got only Rs. 125 lakhs. This shows that the Central Government has given us a stepmotherly treatment. Vellathuval and Mannankandam in Idikki area have been destroyed. The people in that area will have to be rehabilitated. For constructing buildings for them and for replanting cash crops the Central Government will have to give massive aids. So far as the State Government is concerned it has become bankrupt. The annual Plan outlay has been reduced from Rs. 73 crores to Rs. 53 crores. So they are not in a position to give any sort of relief to the people who have suffered due to floods and landslides. Therefore, Sir, we expect that massive central aids will be forthcoming. If we do not get it our position will be very very bad.

19.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 26, 1974/Bhadra 5, 1896 (Saka).